to such units which had signed contracts with machinery manufacturers.

(c) The financial institutions had indicated at the meeting that applications of cooperative sector sugar units for term loans would be considered only after the respective State Governments arrange for clearance of defaults committed by the existing sugar cooperative units whose loans had been guaranteed by the State Governments. As per information recently received from Industrial Finance Corporation of India (IFCI), the cooperative sugar units in Maharashtra have not cleared their defaults.

चीनी का उत्पादन

3368. **श्री राम जेठमलानी :**
श्री वीरेन जे० शाह :

क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चीनी पेराई वर्ष 1992-93 में चीनी का उत्पादन कम रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि इसके मुख्य कारण गन्ने का कम उत्पादन और गन्ना उत्पादकों को समय पर धन का भुगतान करने में विफल रहना है ;

(ग) चीनी पेराई मौसम 1990-91 से 1992-93 सत्र के अन्त में चीनी मिलों की ओर गन्ना उत्पादकों को देय कितनी धनराशि बकाया थी;

(घ) सरकार इस मामले में हस्तक्षेप कर के किसानों को इस बकाया राशि का भुगतान सुनिश्चित करने के मामले में किन कारणों से विफल रही थी;

(ङ) क्या यह भी सच है कि गन्ने का जोत क्षेत्र घटने के कारण गन्ने का उत्पादन पूर्व की तुलना में 10 मिलियन टन कम रहा और चीनी का उत्पादन भी 22 लाख टन कम रहा है ; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा गन्ने के विकास में लगी संस्थाओं के माध्यम से प्रति हैक्टेयर गन्ने की उपज बढ़ाने हेतु प्रोत्साहन न दिये जाने के क्या कारण है और यदि सरकार ने प्रोत्साहन दिया है तो वर्ष 1990-91 और 1992-93 के दौरान गन्ने की प्रति हैक्टेयर उपज क्या थी तथा आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक प्रति हैक्टेयर कितनी उपज लेने का लक्ष्य है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) पेराई वर्ष 1992-93 के दौरान 22-7-1993 तक चीनी का कुल उत्पादन 104.90 लाख टन (अनंतिम) हुआ था जबकि पिछले पेराई वर्ष अर्थात् 1991-92 के दौरान इसी तारीख तक यह उत्पादन 131.62 लाख टन था ।

(ख) चालू चीनी मौसम 1992-93 के दौरान चीनी के उत्पादन में कमी मुख्यतः गन्ने के उत्पादन में कमी उपलब्ध गन्ने का गुड़ तथा खांडसारी सैक्टर की ओर विपथन गन्ने के मूल्य का अधिक बकाया आदि के कारणों से आई है ।

(ग) अपेक्षित सूचना निम्न प्रकार है :-

चीनी मौसम (अक्तूबर से सितम्बर)	गन्ना मूल्य की बकाया राशि (करोड़ रुपये में)	
1990-91	1990-91	160.65
(30-9-1991 को)	1989-90	7.33
	1988-89 तथा पिछले मौसमों का	7.60
	कुल	175.58

1	2	3
1991-92	1991-92	344.83
(30-9-1992 को)	1990-91	3.37
	1989-90 तथा पिछले मौसमों का	3.25
	कुल	351.45
1992-93	1992-93	164.48
(30-6-1993 को)	1991-92	19.47
	1991-92 तथा पिछले मौसमों का	4.57
	कुल	188.52

(घ) गन्ना मूल्य के बकाया का समय पर भुगतान किया जाना सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी मुख्यतः राज्य सरकारों की होती है जिनके पास ऐसे भुगतान के लिए बाध्य करने हेतु आवश्यक अधिकार तथा क्षेत्रीय संगठन हैं । केंद्र सरकार अपनी तरफ से समय-समय पर राज्य सरकारों को ऐसे बकाया के भुगतान के लिए आवश्यक कदम उठाने की सलाह देती रही है ।

इसके अतिरिक्त, केंद्र सरकार व चीनी मिलों की अर्थक्षमता में सुधार के उद्देश्य से 16-2-1993 को चालू मौसम के लिए नई चीनी नीति की घोषणा की थी। राज्य सरकारों को भी गन्ने के मूल्य के संबंध में गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 के उपबंधों के अनुरूप, जिसमें भार्गव फार्मूले के अनुसार अधिक वसूली को चीनी मिल तथा गन्ना उत्पादकों में बराबर बांटने का प्रावधान है, अधिक युक्तियुक्त मूल्य नीति अपनाने की सलाह गई है ।

(ङ) अपेक्षित सूचना निम्न प्रकार है :—

मौसम	गन्ना क्षेत्र (000 हेक्टेयर)	गन्ने का उत्पादन (मिलियन टन)	22 जुलाई तक चीनी का उत्पादन (अनंतिम) (लाख टन में)
1991-92	3736.3	249.3	131.62
1992-93	3650.0	238.0	104.90

(च) सरकार चीनी विकास निधि ो आसान शर्तों पर वित्तीय सहायता देकर न्ने की प्रति-हैक्टेयर उपज बढाने को ोत्साहन दे रही है । तदनुसार, 15-6-1993 तक चीनी फैक्टियों को गन्ना विका ं योजनाओं के लिए चीनी विकास निधि में 533.55 करोड रुपए ऋण के रूप में संवितरित किए गए हैं । देश में 1990-91 तथा 1992-93 मौसमों के दौरान गन्ने की प्रति हैक्टयर उपज क्रमश: 65.5 और 65.2 टन थी । आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक देश में प्रति हैक्टयर औसत गन्ना उपज लेने का लक्ष्य 70.0 टन है ।

Wastage of foodgrains in loading

3369. SHRIMATI VEENA VERMA : SHRI RAJNI RANJAN SAHU : SHRI RAJUBHAI A. PARMAR:

Will the Minister of FOOD be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the news-item appeared in the Pioneer dated June 19, 1993, captioned "Train loads of foodgrains may go waste";

(b) what are the details of the train loads of foodgrains and wagons being shuttled around for want of storage space; and

(c) what steps were taken to prevent wastage of foodgrains?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD (SHRI KALP NATH RAI): (a) Yes, Sir.

(b) There has been no shuttling of foodgrains specials for want of storage space. As a matter of fact the despatch instructions for planned rakes are given to the Railway well in advance. Despatch instructions are given only for those destinations which have the storage space available. Even after loading the rakes, destinations are allocated keeping in view the operational convenience and movability of type of the rakes supplied. As such, the question of shuttling of the loaded rakes on FCI account does not arise.

(c) No wastage of the procured foodgrains is allowed to take place. However, due to very heavy procurement both in the Rabi and Kharif seasons, foodgrain stocks have accumulated in Punjab, Haryana and U.P.

These being the major procuring states, comfortable storage space is required to be created there before the commencement of Kharif 1993-94. The following steps have been taken to ensure clearance of stocks from the procuring States before the commencement of the Kharif 1993-94.

(i) Planning of foodgrains movement from North has been enhanced;

(ii) Zonal Managers have been advised to ensure 90 per cent utilisation of the available storage capacity;

(iii) Storage capacity of 19.11 lakh tonnes both in covered and open has been hired in the consuming States to accommodate the additional stocks;

(iv) Order for approximately 13000 new polythene covers have been placed to properly cover the wheat stocks lying in the open;

(v) Punjab and Haryana Regions have been allowed to undertake road movement of wheat lying in open to Rajasthan region where additional space has been hired.

Integrated Nutrition Education Scheme

3370. SHRI SURINDER KUMAR SINGLA: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) the Non Governmental Organisations which have been aided by Government under the Integrated Nutrition Education Scheme;